SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

एस.डी.जी. स्थानीय स्तर पर विकास को मापने का महत्वपूर्ण साधन

सुदीप कुमावत, पी.एच–डी., सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर, राजस्थान
प्रवीण कुमार, पी.एच–डी., सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सुदीप कुमावत, पी.एच–डी.
प्रवीण कुमार, पी.एच–डी.
E-mail : dr.sudeepkumawat85@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/02/2025
Revised on : 07/04/2025
Accepted on : 16/04/2025
Overall Similarity : 00% on 08/04/2025

शोध सार

विकास की यात्रा में 'कोई भी पीछे ना छूटे' इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए एसडीजी संकेतकों के माध्यम से ग्रामीण विकास में आ रही चुनौतियों को चिह्नित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं का जमीनी स्तर पर गुणात्मक आंकलन करने में मदद मिल रही है। जिन लक्ष्यों में पंचायत समिति पिछड़ी हुई हैं, उन लक्ष्यों को चिह्नित कर उनमें सुधार करने हेतु संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा जिन पंचायत समितियों में इन लक्ष्यों की स्थिति बेहतर है, उनसे प्रेरणा लेकर सभी विभाग अन्य पंचायत समितियों में प्रगति बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

मुख्य शब्द

सतत् विकास लक्ष्य, सर्वांगीण विकास, पंचायत समिति, ग्रामीण विकास.

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आर्थिक–सामाजिक समस्याओं, पर्यावरणीय परिवर्तनों एवं खतरों ने आम–जन को एक बेहतर भविष्य तथा सृमद्ध जीवन की ओर आकर्षित किया है तथा दुनिया के सभी देशों को एकजुट व एक मंच पर लाने का कार्य किया है साथ ही यह विचार करने का समर्थन किया की केवल आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना ही पर्याप्त नही है, अपितु मानव कल्याण हेतु सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं व विकास के विभिन्न आयामों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सर्वांगीण विकास हेतु वैश्विक स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करना वर्तमान में नितान्त आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति को मापने तथा

कौन से लक्ष्य अर्जित कर लिये गये हैं तथा कहाँ अधिक प्रयासों की आवश्यकता है का पता लगाने के लिये एस. डी.जी. स्टेट्स रिपोर्टस् एवं सूचकांकों का निर्माण किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितम्बर, 2015 के अपने शिखर सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्य–2030 कार्यक्रम की नींव रखी जिसे विश्व के 193 देशों द्वारा अपनाया गया। इसमें 17 लक्ष्य 169 टार्गेट सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक अर्जित किया जाना है, ये 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं। प्रारम्भ में, एस.डी.जी. एवं संबद्ध टार्गेट्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क में (जी.आई.एफ.) कुल 244 संकेतकों की पहचान की गई थी। वर्तमान में, जी.आई.एफ. में कुल 248 संकेतक सम्मिलित है। विश्व के सर्वांगीण विकास एवं आमजन के कल्याण हेतु सतत विकास लक्ष्यों को सामुहिक भागीदारी के साथ अर्जित करना, कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि वर्तमान में परम आवश्यक है।

एजेण्डा–2030 के केन्द्र में 5 महत्वपूर्ण आयामः लोग, समृद्धि, ग्रह, भागीदारी एवं शांति हैं जिन्हें 5 पीज् P'S के नाम से जाना जाता है। परम्परागत रूप से, राष्ट्र के विकास का आंकलन प्रमुखतः तीन प्रमुख तत्वों सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के आधार पर किया जाता है। सतत् विकास की अवधारणा ने एजेण्डा 2030 को अपनाने के साथ इसे एक समृद्ध अर्थों में लिया है जिसके तहत परम्परागत अवधारणा में दो महत्वपूर्ण तत्वों भागीदारी एवं शांति को जोड़ा गया है जो कि प्रभावी भागीदारी के माध्यम से आमजन की समृद्धि एवं ग्रह पर शांति सुनिश्चित करने का प्रयास है।

देश में आमजन के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकारे, सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग केन्द्रीय समन्वयक एवं नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को देश में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिये नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमर्वक के निर्माण एवं अद्यतन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार राज्य में इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आयोजना विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत् विकास लक्ष्य कार्यान्वयन केन्द्र की स्थापना की गई है।

गांवों के विकास में सहायक एस.डी.जी.

देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है, इसलिए ग्रामीण विकास, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की खुशहाली एवं समृद्वि का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है अतः देश का विकास करने के लिए सर्वप्रथम गांवों का सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है। देश के ग्रामीण विकास मे स्थानीय स्वशासन की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करने हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किए जा रहे है। प्रशासन के विकेन्द्रीकरण हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा देश की ग्रामीण शासन प्रणाली में आमूल–चूल परिर्वतन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था गांवों में स्थानीय स्वशासन की अहम कड़ी है।

स्थानीय सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन करने के साथ ही आमजन तक सुगमता से योजनाओं का लाभ पहुँचाने मे एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। एसडीजी के अन्तर्गत एक क्षेत्र मे की गई कार्यवाही दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करती है। विकास की यात्रा में 'कोई भी पीछे ना छूटे' इस सिद्वांत पर कार्य करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वर्तमान में स्थानीय स्तर पर एस.डी.जी. लक्ष्यों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा एस.डी.जी. के माध्यम से जिले के ग्रामीण शासन की वर्तमान स्थिति की जांच कर उसे समग्र, समावेशी और सहभागी स्थानीय स्वशासन के रूप में विकसित किया जा सकता है। वर्तमान में एस.डी.जी. के स्थानीयकरण के संदर्भ में पचायती राज विभाग द्वारा अनेक पहले एवं नवाचार किये गये है, जिनमें पंचायत विकास सूचकांक, लोकल इंडीकेटर्स फ्रेमर्वक आदि महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य कार्यक्रम की प्रगति को मापने तथा इन्हें निर्धारित समयावधि में अर्जित करने के लिये देश के राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से एस.डी.जी. इंडिया इण्डेक्स तैयार कर जारी किये जा रहे है। नीति आयोग द्वारा उक्त सूचकांकों के कुल 4 संस्करण अब तक जारी किये गये है। इसी प्रकार राज्य में भी जिलों के मध्य सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 से लगातार हर वर्ष राज्य स्तरीय एस.डी.जी. सूचकांक तैयार कर जारी किये जा रहें है। अब तक इन सूचकांको के 5 संस्करण जारी किये जा चुके हैं।

जयपुर सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक

जिले के सर्वांगीण विकास एवं सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन पूर्णतया प्रतिबद्ध एवं समर्पित है। इस क्रम में सतत् विकास लक्ष्यों की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुये विभिन्न पेरामिटर्स पर प्रगति का पता लगाने के लिये पंचायत समिति वाईज जयपुर एस.डी.जी. इंडेक्स 2024 का निर्माण किया गया है। इसमें एस.डी.जी. इण्डेक्स को गोलवाईज एवं समग्र स्कोर मे विभाजित किया गया है ताकि यह समझने मे मदद मिल सके कि कौन से लक्ष्य अभी प्राप्त किये जा चुके है तथा कहां पर और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक जयपुर की गणना का मूल उद्देश्य जन–कल्याण एवं पंचायत समितियों के मध्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है ताकि लोगों को अच्छा जीवन–स्तर, पर्यावरण की सुरक्षा, असामनताओं में कमी, सबको घर, सबको भोजन, न्याय–शातिं, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में आ रही बाधाओं को इंगित किया जा सके। एस.डी. जी. 2030 को स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर समृद्ध पंचायत समिति एवं समृद्ध जिले के निर्माण की दिशा में एक प्रयास किया गया है। उक्त सूचकांकों की गणना जिले की 16 पंचायत समितियों पर की गयी है।

जिले का सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक तैयार करने में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रयुक्त नीति आयोग के सतत् विकास सूचकांक की गणनाविधि/प्रक्रिया को उपयोग में लिया गया है। जिला स्तरीय सूचकांक का निर्माण 10 लक्ष्यों के कुल 47 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए प्रयुक्त समंक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा स्त्रोतों एवं संबंधित विभागों से सूचनाएं/समंकों से प्राप्त किये गये है। प्रत्येक लक्ष्य के लिये, एस.डी.जी. का स्कोर 0 से 100 के मध्य है, जहाँ 0 समूह में सबसे खराब होता है तथा 100 का तात्पर्य लक्ष्य के सभी टार्गेट्स को प्राप्त कर लेने से है। स्कोर के आधार पर पंचायत समितियों को 4 श्रेणीयों यथा अचीवर (स्कोर 100), फ्रंट–रनर (स्कोर 65–99), परफॉर्मर (स्कोर 50–64), एवं एस्पिरेंट (स्कोर 50 से कम) में वर्गीकृत किया गया है।

एस.डी.आई. स्कोर 50 से कम	एस.डी.आई. स्कोर 65 से कम लेकिन 50 के बराबर	एस.डी.आई. स्कोर 100 से कम लेकिन 65 के बराबर या ज्यादा	एस.डी.आई. स्कोर 100 के बराबर
एस्पिरेंट	परफॉर्मर	फ्रंटरनर	एचीवर

तालिका 1: सूचकांक की गणना में उपयोग में लिए गए संकेतकों का लक्ष्यवार विवरण

क्र.सं.	लक्ष्य	प्रयुक्त संकेतकों का विवरण
1.	लक्ष्य–1 गरीबी का अंत	➢ बीपीएल परिवारों का प्रतिशत। ➢ मनरेगा के तहत रोजगार की पेशकश करने वाले परिवारों का प्रतिशत। ➢ मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। ➢ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाली

		जनसंख्या का अनुपात (कुल पात्र जनसंख्या में से)। ➢ एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का प्रतिशत। ➢ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/पूर्ण घरों का प्रतिशत।
2.	लक्ष्य–2 भुखमरी समाप्त करना	➢ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल पात्र जनसंख्या का अनुपात। ➢ पूरक पोषण प्राप्त करने वाली लक्षित गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत। ➢ आईजीएमपीवाई के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाली जनसंख्या का अनुपात, (नामांकित जनसंख्या में से)। ➢ गेहूं एवं बाजरा की कृषि उत्पादकता। ➢ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कवरेज के साथ सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत रबी एवं खरीफ। ➢ शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत। ➢ जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)।
3.	लक्ष्य–3 आरोग्य एवं कल्याण	➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर आत्महत्या की संख्या। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर सरकारी अस्पताल की सुविधा। ➢ प्रति गांव कार्यरत आशा सहयोगिनियों की औसत संख्या। ➢ संस्थागत प्रसव का प्रतिशत।
4.	लक्ष्य–4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	➢ प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जी.पी.आई.)। ➢ प्रासंगिक बुनियादी सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत (बिजली, पीने का पानी, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय)। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या। ➢ छात्र शिक्षक अनुपात। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर सरकारी कॉलेज संख्या।
5.	लक्ष्य–5 लैंगिक समानता	➢ मनरेगा के तहत कुल महिला दिवसों का प्रतिशत। ➢ प्रति 10000 महिला जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर। ➢ वर्ष के दौरान प्रति 10000 महिलाओं पर दहेज संबंधी अपराध। ➢ लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं)। ➢ प्रति 10000 महिलाओं पर यौन अपराध।
6.	लक्ष्य–6 शुद्ध जल एवं स्वच्छता	➢ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल नल कनेक्शन वाले घरों का प्रतिशत। ➢ ब्लॉक ओडीएफ होने का सत्यापन।
7.	लक्ष्य–9 उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना	➢ भारत नेट के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत का प्रतिशत। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर पंजीकृत एम.एस.एम.ई. इकाइयों की संख्या। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर बी.आर.एन. के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों की संख्या।

8.	लक्ष्य–10 असमानताओं में कमी लाना	➢ मनरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कुल व्यक्ति दिवसों का प्रतिशत। ➢ मनरेगा के तहत कुल व्यक्ति दिवसों का प्रतिशत।
9.	लक्ष्य–12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	➢ कुल उर्वरकों में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रतिशत उपयोग। ➢ प्रति पूंजी कृषि उत्पादन (उत्पादन मीट्रिक टन)।
10.	लक्ष्य–16 शांति, न्याय एवं सुदृढ संस्थाएं	➢ सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल लोगों की संख्या (प्रति 10000 जनसंख्या)। ➢ प्रति 10000 जनसंख्या पर दर्ज कुल आईपीसी अपराध। ➢ जन संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निवारण का प्रतिशत। ➢ प्राप्त आवेदन में से जन्म पंजीकरण का प्रतिशत (पहचान)। ➢ प्राप्त आवेदन में से मृत्यु पंजीकरण का प्रतिशत (पहचान)। ➢ जन–आधार के अंतर्गत कवर की गई जनसंख्या का अनुपात।

जिले की 16 पंचायत समितियों में 72.60 स्कोर के साथ शाहपुरा ब्लॉक शीर्ष पर तथा 62.28 स्कोर के साथ जालसू ब्लॉक सबसे निचले स्थान पर रहा है। जिले की शाहपुरा, जमवारामगढ़, गोविन्दगढ, कोटखावदा, आमेर, जोबनेर, आंधी, किशनगढ़ रेनवाल, सांभर, सांगानेर एवं माधोराजपुरा पंचायत समितियों का प्रदर्शन फ्रंट–रनर श्रेणी का रहा है तथा पंचायत समिति तूंगा, झोटवाडा, चाकसू, बस्सी एवं जालसू का प्रदर्शन परफॉर्मर श्रेणी मे रहा है।

अखिल जयपुर जिले का एस.डी.जी. इंडेक्स में समग्र स्कोर 70.22 (फ्रंट–रनर) रहा है जिले के औसत से अधिक स्कोर वाली पंचायत समितियां शाहपुरा 72.60, जमवारामगढ 71.28, गोविन्दगढ 71.25, एवं कोटखावदा 70.48 है। शेष पंचायत समितियों का स्कोर जयपुर के समग्र स्कोर से कम रहा है। लक्ष्य 3 आरोग्य एवं कल्याण में शाहपुरा का स्कोर 85.34 के साथ प्रथम रहा तथा चाकसू 47.36 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा है। लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना में सांगानेर ब्लॉक का स्कोर 100 सबसे अधिक रहा तथा किशनगढ रेनवाल का स्कोर 34.87 के साथ सबसे कम रहा है। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन मे शाहपुरा ब्लॉक का स्कोर 91.46 सबसे अधिक रहा। सूचकांको में ब्लॉकस के लक्ष्यवार प्रदर्शन को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तलिका 2: पंचायत समितिवार समग्र एस.डी.जी. इंडेक्स स्कोर एवं रैंक

ब्लॉक	स्कोर	रेंक
शाहपुरा	72.60	01
जमवारामगढ़	71.28	02
गोविन्दगढ़	71.25	03
कोटखावदा	70.48	04
आमेर	69.48	05
जोबनेर	68.36	06
ऑधी	67.25	07
किशनगढ रेनवाल	66.21	08
सांभर	66.00	09
सांगानेर	65.83	10
माधोराजपूरा	65.79	11
तुंगा	64.65	12

झौटवाडा	64.63	13
चाकसू	63.61	14
बस्सी	62.56	15
जालसू	62.28	16
जयपुर ग्रामीण	70.22	

(स्त्रोतः जयपुर एसडीजी सूचकांक 2024)

निष्कर्ष

एस.डी.जी. सूचकांक, ग्रामीण विकास में आ रही चुनौतियों को पंचायत समितिवार चिह्नित करके उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में भूमिका का निंवहन करेगें। सरकार द्वारा विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है लेकिन जमीनी–स्तर पर उनका गुणात्मक आंकलन करने के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक काफी उपयोगी सिद्ध होगें। जिन संकेतकों में पंचायत समिति पिछडी हुई है, उन संकेतकों में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों से प्रभावी समन्वय के माध्यम से उनमें वांछित प्रगति लायी जावेगी तथा जिन पंचायत समितियों में स्थिति अच्छी है उनसे प्रेरणा लेकर अन्य पंचायत समितियों के विभाग अपनी प्रगति बढ़ाने के प्रयास करेगें।

एस.डी.जी. सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी तथा पंचायत समिति के जी.पी.डी.पी. प्लान में उन कार्यों को प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाएगा, ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। वास्तव में एस.डी.जी. सूचकांक का निर्माण एस.डी.जी. के केन्द्रीय वाक्य 'कोई भी पीछे ना रहे' के सिद्वांत का अनुसरण कर जिले की समस्त पंचायत समितियों का विकास करना है।

गांवों के विकास का, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति सशक्त माध्यम है इसलिए पंचायत समिति स्तर पर सभी विभागों को ग्राम पंचायतवार डाटा के संकलन की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन व मूल्यांकन किया जा सके।

वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु बहुत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वैश्विक लक्ष्यों व संकेतकों के आधार पर हमें मात्रात्मक की बजाय गुणात्मक परिणामों पर ध्यान देना होगा। आज ग्रामीण विकास की संकल्पना को परिपूर्ण करने हेतु एस.डी.जी. संकेतकों की समझ व जानकारी गांव–ढाणी तक पहुँचाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

संदर्भ सूची

1. एसडीजी सेल, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।
2. आर्थिक समीक्षा वर्ष 2024–25 राजस्थान।
3. आर्थिक समीक्षा 2024–25 भारत।

****